



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1944 (श10)  
(सं० पटना 173) पटना, शुक्रवार, 01 अप्रील 2022

सं० प्र02/बो०फ०-15/08-1011  
ऊर्जा विभाग

संकल्प

16 मार्च 2022

विषय:-

(क) कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैती (भागलपुर) में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (BSPGCL) द्वारा 80:20 वित्तीय पोषण (Funding Mechanism) के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजना के अधिष्ठापन की सैद्धांतिक स्वीकृति।

एवं

(ख) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) द्वारा उक्त दोनों स्थलों पर ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु व्यय की गई राशि 1598.18 करोड़ (एक हजार पाँच सौ अनठानवे करोड़ अठारह लाख) रुपये (सेवा शुल्क सहित) ऊर्जा विभाग द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा उक्त भूमि का स्वामित्व ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित करने तथा ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 636 दिनांक 12.03.1991 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 को इस हद तक शिथिल करते हुए 01 (एक) रुपये प्रति वर्ष के सांकेतिक दर पर 33 वर्षों के लिए लीज पर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या-2838 दिनांक-09.11.2021 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम, 2013 की धारा-99 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य के कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैती (भागलपुर) में ताप विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. कजरा एवं पीरपैती में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि से दोनों परियोजना स्थलों पर क्रमशः 1204.9025 एकड़ एवं 1020.60 एकड़ भूमि अधिग्रहित है।

3. विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-07.04.2021 को कजरा एवं पीरपैती में सौर ऊर्जा परियोजना के स्थापना संबंधी आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त परियोजनाओं की भूमि हेतु ऊर्जा विभाग अधियाची विभाग है, ऊर्जा विभाग के द्वारा भू-अर्जन में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव लाया जाय।

4. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) द्वारा ऊर्जा विभाग को बाधा मुक्त (Encumbrance Free) भूमि के हस्तांतरण के पश्चात कजरा एवं पीरपैती में भूमि अधिग्रहण हेतु व्यय की गई राशि 1531.59 करोड़ तथा देय सेवा शुल्क 66.59 करोड़ अर्थात् कुल 1598.18 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) को प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके लिए ऊर्जा विभाग को पूँजीगत व्यय के अंतर्गत बजटीय प्रावधान किया जाना होगा।

5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 636 दिनांक 12.03.1991 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 को इस हद तक शिथिल करते हुए कजरा एवं पीरपैती दोनों स्थलों पर सौर ऊर्जा परियोजना हेतु उपलब्ध भूमि को 33 (तैतीस) वर्षों के लिए 01 (एक) रुपये प्रतिवर्ष के सांकेतिक दर पर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (BSPGCL) को लीज पर उपलब्ध कराया जायेगा। भूमि का स्वामित्व ऊर्जा विभाग के पास ही रहेगा। इन दोनों सौर ऊर्जा परियोजना के विकासन में भूमि की लागत की छूट का लाभ राज्य के उपभोक्ताओं को सस्ते टैरिफ के रूप में प्रदान किया जा सकेगा।

6. केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) वर्तमान के 17% से बढ़कर आने वाले समय में इसके दुगुणा से अधिक होने की संभावना है।

7. इन दोनों परियोजना स्थलों पर प्रत्येक में लगभग 200–250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का प्रस्ताव है, जो राज्य के स्वयं के प्रक्षेत्र में सबसे बड़ी क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजना होगी। इससे राज्य के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित नवीकरणीय क्रय दायित्व (Renewable Purchase Obligation) को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

8. इस परियोजना से उत्पादित सौर ऊर्जा को सायंकाल के पश्चात, जिस समय राज्य की विद्युत मांग अधिकतम स्तर पर रहती है, उपलब्ध कराने हेतु उत्पादन के साथ-साथ सौर ऊर्जा का भंडारण (Battery Storage) का प्रावधान करने पर सौर ऊर्जा का अहर्निश उपयोग किया जा सकेगा।

9. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (BSPGCL) द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं में आने वाली लागत के लिये 80:20 वित्तीय पोषण के अन्तर्गत संसाधन प्राप्त किये जायेंगे, जिसमें 80 प्रतिशत की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वरूप प्राप्त किया जायेगा तथा 20 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार से पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी (equity) स्वरूप प्राप्त होगा।

10. उक्त के आलोक में –

(क) कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैती (भागलपुर) में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (BSPGCL) द्वारा 80:20 वित्तीय पोषण (Funding Mechanism) के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजना के अधिष्ठापन की सैद्धांतिक स्वीकृति।

एवं

(ख) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) द्वारा उक्त दोनों स्थलों पर ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु व्यय की गई राशि 1598.18 करोड़ (एक हजार पाँच सौ अठानवे करोड़ अठारह लाख) रुपये (सेवा शुल्क सहित) ऊर्जा विभाग द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा उक्त भूमि का स्वामित्व ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित करने तथा ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 636 दिनांक 12.03.1991 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 को इस हद तक शिथिल करते हुए 01 (एक) रुपये प्रति वर्ष के सांकेतिक दर पर 33 वर्षों के लिए लीज पर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से

संजीव हंस,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 173-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>